Q: हाल में केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. यह अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहता है।
2. निजी क्षेत्र की भागीदारी इसरो को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगी।
3. नीति निजी क्षेत्र को एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देगी।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: a
व्याख्या:

- नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है।
- नीति निजी क्षेत्र को एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी जिसमें उपग्रह, रॉकेट और लॉन्च वाहन बनाना, डेटा संग्रह और प्रसार शामिल है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से इसरो को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

Q: हाल के एक अध्ययन के अनुसार देश के भूजल में कमी का 95 प्रतिशत हिस्सा उत्तर भारत में है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. अत्यधिक पम्पिंग भूजल की कमी का कारण नहीं हो सकता।
2. अवक्षेपण में कमी तथा नलकूपों में तीव्र वृद्धि।
3. मानसून से पहले और बाद के मौसम में चावल और गेहूं की फसलों की सिंचाई।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: b
व्याख्या:

- शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि भारत में भूजल की कमी तब तक जारी रहेगी जब तक कि अत्यधिक पम्पिंग को सीमित नहीं किया जाता है, जिससे भविष्य में पानी की स्थिरता के मुद्दे सामने आएंगे।
- अवक्षेपण में गिरावट और भूजल निकासी के लिए नलकूपों में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप भूजल की अत्यधिक पंपिंग हुई है, जिससे उत्तर भारत में भूजल संसाधनों में भारी कमी आई है।
- उत्तर और मध्य भारत में भूजल का उपयोग मुख्य रूप से मानसून से पहले और बाद के मौसम में चावल और गेहूं की फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है।
- गैर-नवीकरणीय (अस्थिर) पम्पिंग का भूजल भंडारण पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है, जिससे जल स्तर गिर जाता है।

Q: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. कांस्टेबलों के पद के लिए रिक्तियों वाले बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था।
2. स्वीकृत पदों की तुलना में बिहार में रिक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2
d) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

- पुलिस कांस्टेबलों के मामले में जनवरी 2022 तक पश्चिम बंगाल का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिसमें स्वीकृत पदों के 44.1 प्रतिशत पद खाली थे। वहीं केरल स्वीकृत पद संख्या के 4.6 प्रतिशत कॉन्स्टेबल रिक्तियों के साथ टॉप पर था।
- पुलिस अधिकारियों (सिविल के साथ-साथ जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस) के लिए, बिहार में स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 53.8 प्रतिशत रिक्तियों का उच्चतम प्रतिशत है।

Q: हाल में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का "प्री-ड्राफ्ट"संस्करणजारीकिया।प्रमाणोंपरफोकसकेसंबंधमेंनिम्नलिखितकथनोंपरविचारकरें:

1. प्रत्यक्ष
2. उपमान
3. अनुपलब्धि

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

व्याख्या:

- दस्तावेज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में मूल्यों और इसकी "जड़" को शामिल करना है।
- दस्तावेज़ आगे कहता है कि यह छात्रों को ज्ञान के सच्चे स्रोतों से परिचित कराने की ओर झुकता है, जो कि प्राचीन भारतीयों की दार्शनिक व्यस्तता रही है। ये स्रोत छह प्राणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:
  a) प्रत्यक्ष, पांच इंद्रियों के माध्यम से धारणा के रूप में व्याख्या की गई;
  b) अनुमान, जो नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनुमानों का उपयोग करता है;
  c) ग) उपमान, जो सादृश्य और तुलना के माध्यम से जानना है;
  d) अर्थपट्टी, जिसमें परिस्थितिजन्य निहितार्थ के माध्यम से जानना शामिल है,

e) अनुपलब्धि, जिसमें गैर-अस्तित्व की धारणा शामिल है, और
f) सबदा, जिसे दस्तावेज़ समझाता है, "कुछ ऐसा है जो प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के माध्यम से एक व्यक्ति सीधे तौर पर सभी वास्तविकता का एक अंश ही जान सकता है, लेकिन अन्य विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहिए, जिसे हजारों साल पहले स्वीकार किया गया था"।

Q: हाल में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन अधिसूचित किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सत्यापित प्रकाशन
2. स्व-नियामक निकाय
3. ऑनलाइन गेम में असली पैसा शामिल नहीं है

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- माता-पिता, स्कूल के शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, गेमर्स और गेमिंग उद्योग संघों, बाल अधिकार निकायों आदि सहित कई हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया है।
- संशोधित नियमों के अनुसार, बिचौलियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी भी ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा न करने के लिए उचित प्रयास करें, जिससे उपयोगकर्ता को नुकसान हो सकता है, या जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित एक ऑनलाइन गेमिंग स्व-नियामक निकाय/निकाय द्वारा अनुमति-योग्य ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है।
- स्व-नियामक निकाय के पास पूछताछ करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि ऑनलाइन गेम में किसी भी परिणाम पर दांव लगाना शामिल नहीं है, कि ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ और गेम नियमों का अनुपालन करता है, प्रवेश करने के लिए सक्षम होने के लिए कानून के तहत आवश्यकताएं एक अनुबंध में (वर्तमान में 18 वर्ष), और स्व-नियामक निकाय द्वारा उपयोगकर्ता के जुआ खेलने की लत से नुकसान के खिलाफ सुरक्षा उपायों के बारे में बनाया गया एक ढांचा, जिसमें मनोवैज्ञानिक नुकसान, माता-पिता के नियंत्रण के माध्यम से सुरक्षा के उपाय, आयु-रेटिंग तंत्र और उपयोगकर्ताओं को जोखिम से बचाने के उपाय शामिल हैं।
- संशोधित नियम वास्तविक धन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संबंध में ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों पर अतिरिक्त दायित्व भी डालते हैं।
- इनमें ऐसे खेलों पर स्व-नियामक निकाय द्वारा सत्यापन चिह्न प्रदर्शित करना; अपने उपयोगकर्ताओं को जमा धनराशि की वापसी या भुगतान, जीत के निर्धारण और वितरण, शुल्क और देय अन्य शुल्कों के लिए नीति के बारे में सूचित करना; उपयोगकर्ताओं के केवाईसी विवरण प्राप्त करना; और उपयोगकर्ताओं को तीसरे पक्ष द्वारा क्रेडिट या वित्तपोषण नहीं करना शामिल है।